पूर्ण बेंच

सिविल विविध

न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, बीएस ढिल्लों

और सुरिंदर सिंह के समक्ष।

अर्जुन सिंह नेगी, - याचिकाकर्ता।

बनाम

भारत संघ, आदि, - उत्तरदाता।

1976 की सिविल रिट याचिका संख्या 30।

15 सितंबर, 1976।

प्राकृतिक न्याय - विभागीय पदोन्नति समिति उच्च पद पर पदोन्नति के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों के मामलों की जांच करती है - ऐसे उम्मीदवार - चाहे वे सुनवाई के हकदार हों।

माना जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोषणा करना आसान है, लेकिन उनकी सटीक सीमा को परिभाषित करना बहुत कम आसान है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवश्यक तत्वों में से एक *ऑडी अल्टरम पार्टम है,* अर्थात, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। हालांकि, इस सिद्धांत का आवेदन एक ऐसे मामले की ओर आकर्षित होता है जहां विवाद के लिए दो विरोधी पक्ष होते हैं। विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष वास्तव में कोई दो चुनाव लड़ने वाले पक्ष नहीं हैं जब उसे नियमित आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति के संबंध में मामला पता चलता है। विभागीय पदोन्नति समिति को एक निश्चित पद को भरने के उद्देश्य से पदोन्नति के मामले पर विचार करना है और तुलनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य से न केवल वरिष्ठता बल्कि

सभी पात्र उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, कार्य और आचरण की समीक्षा करने के लिए बुलाया जाता है। समिति को स्वयं को दो उम्मीदवारों के बीच विवाद या उम्मीदवारों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रखना है। ऐसी समिति के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसके निर्णय के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों को कान लगाने की आवश्यकता हो। *इसलिए ऐसी स्थिति में ऑडी अल्टरम पार्टम का* सिद्धांत न तो लागू होता है और न ही उपलब्ध होता है। इस प्रकार एक उच्च पद पर पदोन्नति के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों के मामलों की जांच करते समय एक विभागीय पदोन्नति समिति को ऐसे प्रत्येक उम्मीदवार को सुनने की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 4)

पृथ्वी राज मेहरा बनाम पृथ्वी *पंजाब राज्य,* 1968, एस.एल.आर. 887 को निरस्त कर दिया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी मंडमस *या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए: -*

(१) *मामले के पूरे रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए,*

(२) *अनुलग्नक पीए में दिए गए आदेश को रद्द किया जाए;*

(३) *यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता एक लेखाकार बना हुआ है;*

(४) *याचिकाकर्ता को पीए के लिए अनुलग्नक पी -1 की मूल प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए;*

(५) *याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V के तहत आवश्यक पांच दिनों के नोटिस से छूट दी*

जाए;

(६) *यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर*

सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे;

(७) *यह माननीय न्यायालय वेतन, वरिष्ठता आदि की बकाया राशि जैसी सभी परिणामी राहतें भी प्रदान कर सकता है;*

(८) *आगे यह प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका के निपटान तक, अनुबंध पीए में आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाए। हालांकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अभी तक लेखाकार के पद का प्रभार नहीं सौंपा है।*

(९) *इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।*

जे. एल. गुप्ता, एडवोकेट, जी. सी. गुप्ता एडवोकेट के साथ; *याचिकाकर्ता* के लिए ।

कुलदीप सिंह, प्रतिवादी के लिए *वकील* 1 और 2.

आदेश

सुरिन्दर सिंह, जे.–(1) आगे बढ़ने की राह का क्रम व्यवहार-समझ-न्याय है। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए। याचिकाकर्ता अर्जन सिंह नेगी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में कहा है कि उन्हें निदेशक, जनगणना संचालन, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय में 14 अप्रैल, 1969 को लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में भर्ती किया गया था। उन्हें 3 सितंबर, 1970 को *तदर्थ* आधार पर और उसके बाद 31 अक्टूबर, 1971 को नियमित आधार पर अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया था। रैंक में अगला पद

लेखाकार का है। एक नियमित अपर डिवीजन क्लर्क जिसके पास तीन साल की सेवा है, लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। आई. सी. सेठिया (तीसरे उत्तरदाता) को वर्ष 1970 में अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में सीधे उसी कार्यालय में भर्ती किया गया था। याचिकाकर्ता से पहले शामिल होने के बाद, तीसरा प्रतिवादी निश्चित रूप से उससे वरिष्ठ था। 25 जुलाई, 1972 को एक आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा तीसरा प्रतिवादी जो सहायक लेखाकार के रूप में काम कर रहा था, उसे कैशियर के रूप में तैनात किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता जो उस समय कैशियर के रूप में काम कर रहा था; सहायक लेखाकार के रूप में काम करने के लिए कहा गया था। यह विवादित नहीं है कि सहायक लेखाकार और कैशियर के दोनों पद अपर डिवीजन क्लर्क के एक ही कैडर के भीतर हैं। स्थानांतरण का आदेश (प्रति अनुलग्नक 'पी-2') इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि तीसरे प्रतिवादी ने लेखा कार्य में प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया था और लिखित में दिया था कि वह लेखाकार के पद पर पदोन्नत होने में रुचि नहीं रखता था। इसलिए, आदेश में कहा गया है कि तीसरे प्रतिवादी ने लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए अपने अधिकारों को खो दिया था। 24 जुलाई, 1973 को जनगणना संचालन निदेशक द्वारा एक आदेश पारित किया गया था (कॉपी अनुलग्नक पी -3) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को "अस्थायी और सख्ती से तदर्थ आधार" पर एकाउंटेंट के रूप में पदोन्नत किया गया था। अक्तूबर, 1975 में लेखाकार के पद पर एक नियमित पदधारी की नियुक्ति का अवसर उत्पन्न हुआ। इसलिए, 26 दिसंबर, 1975 को एक आदेश पारित किया गया (कॉपी अनुलग्नक पी

-4) तीसरे प्रतिवादी को एक लेखाकार के रूप में पदोन्नत किया गया, हालांकि अस्थायी क्षमता में, क्योंकि उसे दो साल के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था। उसी आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता जो *तदर्थ आधार पर लेखाकार के रूप में काम कर रहा था*, को अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर वापस कर दिया गया था। इस आदेश ने याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में प्रवेश कराया है।

(दो) आधिकारिक उत्तरदाताओं ने कार्रवाई का विरोध किया है। जनगणना संचालन, हरियाणा के उप निदेशक श्री अर्दमन सिंह द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में यह कहा गया है कि तीसरे प्रतिवादी ने लेखाकार के पद पर पदोन्नत होने के लिए अनिच्छा दिखाई थी, क्योंकि प्रासंगिक समय में, मसौदा भर्ती नियमों के अनुसार, वह अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए भी पात्र था जो लेखाकार की तुलना में अधिक था। तथापि, फरवरी, 1973 में अंतिम भर्ती नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद स्थिति बदल गई। इन नियमों के अनुसार, एक अपर डिवीजन क्लर्क, केवल लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था और वह भी तब जब उसने अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में कम से कम तीन साल की सेवा की हो। इन नियमों के मद्देनजर तीसरे प्रतिवादी की पदोन्नति के अन्य सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया कि उन्हें लेखाकार के पद पर पदोन्नत करने के लिए विचार किया जा सकता है, जिसे उन्होंने पहले अस्वीकार कर दिया था। तीसरे प्रतिवादी के अभ्यावेदन पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित आधार पर लेखाकार के पद को भरने के समय विचार किया गया था, साथ ही याचिकाकर्ता

सहित अन्य सभी अधिकारियों के मामले भी शामिल थे। उचित विचार के बाद, तीसरे प्रतिवादी को उस पैनल में नंबर 1 पर रखा गया था जिसे लेखाकार के पद पर चयन के लिए तैयार किया गया था और उसे पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता के संबंध में, यह कहा गया था कि उन्हें केवल *तदर्थ* आधार पर लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया था और इस नियुक्ति को विभागीय पदोन्नति समिति का अनुमोदन प्राप्त करके नियमित नहीं किया गया था, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर लेखाकार के पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन करने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी था।

(तीन) श्री जे. एल. गुप्ता, विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की शिकायत को आवाज दी और ऐसा करते हुए, आक्षेपित आदेश (कॉपी अनुबंध पी -4) के खिलाफ अपने हमले को सीमित कर दिया, एकमात्र आधार पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर वापस आने से पहले कभी भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। विवाद की उछाल का परीक्षण करना होगा।

(चार) विद्वान वकील ने प्राकृतिक न्याय की बात की है। प्राकृतिक न्याय वास्तव में क्या है? प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की घोषणा करना आसान है, लेकिन उनकी सटीक सीमा को परिभाषित करना बहुत कम आसान है। (एवरशेड, एम. आर. *एबॉट* बनाम *सुलिवन* (1957) आई.के.बी. 189, पृष्ठ 195 पर)। तथापि, यह बिना किसी शर्त के कहा जा सकता है कि विधिक कोषागारों से उपलब्ध आदेशों के

अर्जुन सिंगिक्स नेगी ***बनाम*** भारत संघ, आदि (सुरिंदर सिंह, जे।

आलोक में, यदि मैं इस शब्द का प्रयोग करूं, तो प्राकृतिक न्याय के मुख्य सिद्धांतों को दो आवश्यक तत्वों में संक्षेप ति किया जा सकता है (क) कोई भी अपने आप में न्यायाधीश नहीं होगा।

मामले और (ख) *ऑडी अल्टरम पार्टम,* यानी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जाहिर है, यह तत्व (बी) है जिसे विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क के समर्थन में लागू करने की मांग की जाती है। हालांकि, सिद्धांत का आवेदन केवल उस मामले के लिए आकर्षित होगा जहां विवाद के लिए दो विरोधी पक्ष हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वास्तव में दो चुनाव लड़ने वाले पक्ष थे, जो नियमित आधार पर लेखाकार के पद पर पदोन्नति के मामले को देख रहे थे। जवाब स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। एक विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे एक निश्चित पद को भरने के उद्देश्य से पदोन्नति के मामले पर विचार करना है, को तुलनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य से न केवल वरिष्ठता बल्कि सभी पात्र उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, कार्य और आचरण की समीक्षा करने के लिए बुलाया जाता है। समिति को याचिकाकर्ता और तीसरे प्रतिवादी के बीच विवाद तक खुद को सीमित नहीं रखना है, या उस मामले के लिए, याचिकाकर्ता और कुछ अन्य उम्मीदवारों के बीच। वास्तव में, वर्तमान मामले में समिति के समक्ष ऐसा कोई विवाद नहीं था, जिसके निर्णय के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों को ध्यान देना आवश्यक था। निश्चित रूप से, एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जहां याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निर्देशित शिकायत या अभ्यावेदन पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ऐसे मामले में यह समिति का परम कर्तव्य होगा कि वह याचिकाकर्ता की निंदा करने से पहले उसे सुने। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि रिटर्न में कहा गया है, समिति ने याचिकाकर्ता सहित सभी पात्र उम्मीदवारों के गुणों पर उचित विचार किया था। ऐसी स्थिति में *ऑडी अल्टरम पार्टम का* सिद्धांत न तो लागू होता है, न ही उपलब्ध होता है।

(पाँच) विद्वान वकील ने वास्तव में पृथ्वी राज मेहरा *बनाम*

पंजाब राज्य *(1) में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए शरण* मांगी है, जहां विद्वान न्यायाधीश ने उक्त विभाग से संबंधित नियमों के तहत गठित लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), सार्वजनिक स्वास्थ्य की विभागीय स्क्रीनिंग समिति के कार्यों के बारे में मामले से निपटते हुए शरण मांगी थी। उनका विचार था कि जिन अधिकारियों के मामलों की जांच समिति द्वारा की जानी है, वे सुनवाई के अवसर के हकदार हैं। उनका यह भी विचार था कि यदि अधिकारियों को यह अवसर नहीं दिया जाता है, तो प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के नियमों का उल्लंघन होता है। इस निष्कर्ष के समर्थन में तर्क यह है कि समिति को एक योग्य उम्मीदवार को प्रतिस्थापित करने की शक्ति है और उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया की जानी थी। इस प्रकार, लोक सेवा आयोग को सिफारिश करने से पहले समिति को प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों को सुनना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने *जगदीश पांडे* बनाम *बिहार विश्वविद्यालय के चांसलर और अन्य* (2) में की गई कुछ टिप्पणियों पर भी भरोसा किया। हालांकि, उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले और डिवीजन बेंच के समक्ष के मामले दोनों से बहुत अलग थे। *जगदीश पांडे के मामले* (सुप्रा) में, बिहार विधानमंडल ने 1962 के बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम संख्या 13 को पारित किया था। उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्व विधान के होते हुए भी, विनिदष्ट तिथि को या उससे पहले की गई किसी शिक्षक की प्रत्येक नियुक्ति, बर्खास्तगी, निष्कासन इत्यादि, ऐसे आदेशों के अध्यधीन होगा,

(1) डब्ल्यू सर्विसेज लॉ रिपोर्टर 887।

(2) ए.आई.आर. 1968 सुप्रीम कोर्ट 353.

जो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सिफारिश पर उसके संबंध में पारित करे। उस मामले में अपीलकर्ता, जगदीश पांडे को एक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया था। इस नियुक्ति के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका के माध्यम से दी गई चुनौती विफल हो गई थी। 1962 के बिहार अधिनियम 13 के लागू होने के बाद, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने जगदीश पांडे को नवंबर, 1962 तक ही प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी मंजूरी से अवगत कराया, या आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार के शामिल होने तक, जो भी पहले हो। इसके बाद, यह महसूस करते हुए कि अपीलकर्ता के संबंध में चांसलर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी जा सकती है, आयोग ने पहले के आदेश को संशोधित करने की दृष्टि से अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग की सिफारिश पर, चांसलर ने 18 अगस्त, 1962 को एक और आदेश पारित किया, जहां तक यह अपीलकर्ता से संबंधित था, जिसने इस सेवा की शर्तों को इस हद तक संशोधित किया कि उसे एक निर्दिष्ट समय के भीतर द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री प्राप्त करने की आवश्यकता थी, जिसमें विफल रहने पर उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना था। यदि इस व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि बिहार अधिनियम की धारा 4 में यह निहित है कि आयोग को अपनी सिफारिश करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार संबंधित शिक्षक का पक्ष सुनना चाहिए। वास्तव में, ये टिप्पणियां इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की गई थीं कि सुनवाई के लिए एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी, अधिनियम की धारा 4 को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण के रूप में रद्द नहीं

किया जा सकता है। इन टिप्पणियों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता था कि विभागीय पदोन्नति के प्रयोजन रा्थ भी प्राकृतिक न्याय के नियमों के तहत सभी उम्मीदवारों के लिए विभागीय समिति द्वारा सुनवाई अनिवार्य है। *पृथ्वी राज मेहरा के मामले* (सुप्रा) का निर्णय करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, हमारे लिए इस विषय पर व्यक्त किए गए विचार को स्वीकार करना संभव नहीं है और यह माना जाना चाहिए कि उस सीमा तक निर्णय सही कानून निर्धारित नहीं करता है।

(छः) बार में उद्धृत कुछ अन्य अधिकारियों का इस मुद्दे से कोई संबंध नहीं था और इस तरह इन पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(सात) प्राकृतिक बोझ के कारण, न्याय का तराजू याचिकाकर्ता के पक्ष में बिल्कुल नहीं झुकता है। रिट याचिका खारिज की जाती है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

न्यायाधीश ओ चिन्नप्पा रेड्डी, मैं सहमत हूं।

न्यायाधीश भोपिंदर सिंह ढिल्लों, मैं भी सहमत हूं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा